(ख) वर्ष 1966-97 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने अल्मोड़ा, पौड़ी तथा चमोली जिलों में क्रमशः 47, 53 तथा 27 बसे हुए गांवों के विद्युतीकरण का कार्यक्रम बनाया है।

(ग) जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की सूचना के अनुसार जिला सलाहकार समिति द्वारा चुने हुए गांवों के आकार पर ध्यान न देते हुए इन्हें विद्युतीकरण के लिए हाथ में लिया जाएगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Additional Capacity to Meet Energy Requirement

2044. SHRI AKHILESH DAS: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Working Group on Power has projected 55761 MWs additional capacity to get over the prevailing energy shortages;

(b) whether this additional capacity for power is likely to be the target in the 9th Five Year Plan;

(c) what is the estimated outlay requirement for power sector in that plan;

(d) whether target set for the 8th Five Year Plan has been achieved or is likely to be achieved;

(e) if not, the details in this regard; and

(f) whether the Ninth Five Year Plan for power is being prepared by the Working Group on the basis of the internal resources; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) to (c) and (f) The Working Group on Power for 9th Plan has recommended a capacity addition of 57735MW during 9th Plan to meet the power requirements projected by 15th Electric Power Survey Committee.The targets for the Ninth Plan and outlay are still under finalisation by the Planning Commission.

(d) and (e) As against a capacity addition programme of 30537.7 MW during the Eighth Plan, the achievement is expected to be around 17668 MW. The main reasons for shortfall have been paucity of resources with the States, rehabilitation & resettlements issues, law and order etc.

राज्य बिजली बोर्डों के घाटे

2045. **श्री गोपाल सिंह सोलंकी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994, 1995 और 1996 में 31 दिसम्बर, तक गुजरात सहित विभिन्न राज्यों के विद्युत बोर्डों को, वार्षिक रिपोर्टों और केन्द्रीय सरकार के आंकलन के अनुसार, बिजली के उत्पादन एवं वितरण में तुलनात्मक दृष्टि के लोगों से कितना-कितना घाटा या लाभ हुआ;

(ख) क्या सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों के कार्य निष्पादन में लगातार आई गिरावट के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ कोई बैठक की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) कुछ रा०बि०बो० के लेखों का निर्धारण न होने की वजह से, वर्ष 1995-96 हेतु सभी रा०बि०बो० की अधिशेष / कमी उपलब्ध नहीं है। तथापि, गुजरात राज्य बिजली बोर्ड सहित रा०बि०बो० की अधिशेष / कमी ग्रामीण विद्युतीकरण आर्थिक सहायता को गणना में लेकर, जैसा कि वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 हेतु लेखों में प्रदान किया गया है, क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में संलग्न है **(नीचे देखिए)**।

(ख) और (ग) 3 दिसम्बर, 1996 को आयोजित मुख्यमंत्रियों / विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में इस बात को स्वीकार किया गया कि राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति तीव्रता से गिर रही है तथा विद्युत क्षेत्र के भावी विकास को व्यवहार्य राज्य बिजली बोर्डों तथा राज्य बिजली बोर्डों के प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन में सुधार के बगैर नहीं बनाए रखा जा सकता।

(घ) अपनाए गए उपचारात्मक उपायों में केन्द्रीय और राज्य नियामक आयोग की स्थापना करना, खुदरा टैरिफ को युक्तियुक्त बनाना, उत्पादन, पारेषण और वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी, केन्द्रीय एजेंसियों की भूमिका की समीक्षा करना, वन्य स्वीकृति जारी करने हेतु राज्यों को और शक्ति प्रदान करना, रा०बि०बो० की प्रबंधकीय पद्धतियों में सुधार करना, भौतिक मानदण्डों में सुधार करना, सह-उत्पादन / कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना करना, जल विद्युत पर जोर देना, इत्यादि शामिल है।

विवरण-I

वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान रा०बि०बो० का अधिशेष / घाटा (आरई आर्थिक सहायता को ध्यान में रखते हुए जैसा कि लेखों में प्रावधान किया गया है।) दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	रा०बि०बो० का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1.	आंध्र प्रदेश	79.45	86.99	87.25
2.	बिहार	191.19	442.65	-80.32
3.	गुजरात	89.79	92.26	105.94
4.	हरियाणा	-335.66	-410.90	16.16
5.	हि०प्र०	11.82	14.61	18.56
6.	कर्नाटक	32.21	33.87	43.06
7.	केरल	18.42	24.12	21.88
8.	मध्य प्रदेश	101.01	118.24	132.40
9.	महाराष्ट्र	272.16	288.90	320.78
10.	उड़ीसा	25.94	29.98	24.90
11.	पंजाब	-117.53	-117.91	-5.53
12.	राजस्थान	65.04	70.12	77.07
13.	तमिलनाडु	225.10	255.54	347.75
14.	उत्तर प्रदेश	213.86	61.23	258.44
15.	पश्चिम बंगाल	-28.35	17.81	18.47
16.	असम	-70.68	144.73	-269.81
17.	मेघालय	-8.27	-4.79	-20.18
	जोड़	765.50	1117.45	1096.82

विवरण-II

वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान राज्य बिजली बोर्डों के अधिशेषों / घाटे (आरई आर्थिक सहायता, जैसा कि लेखों में प्रावधान किया गया है, की गणना न करते हुए) को दर्शाने वाला विवरण।

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	रा०बि०बो०	1992-93	1993-94	1994-95
1.	आंध्र प्रदेश	79.37	86.86	-828.96
2.	बिहार	-242.41	280.65	-300.11
3.	गुजरात	-537.93	-492.35	-550.28
4.	हरियाणा	-370.90	-482.68	-98.92

क्रम सं॰	रा॰बि॰बो॰	1992-93	1993-94	1994-95
5.	हि॰प्र॰	11.82	14.61	17.67
6.	कर्नाटक	-19.49	-1.89	-164.18
7.	केरल	18.40	24.12	13.25
8.	मध्य प्रदेश	-279.04	-297.01	-382.40
9.	महाराष्ट्र	272.00	288.89	328.75
10.	उड़ीसा	23.49	-196.05	-136.08
11.	पंजाब	-460.73	-499.35	-427.48
12.	राजस्थान	-221.43	-354.82	-411.05
13.	तमिलनाडु	-231.96	-301.56	-2.31
14.	उत्तर प्रदेश	-691.46	-1090.20	-978.25
15.	पश्चिम बंगाल	-96.42	-55.38	-78.66
16.	असम	-134.75	-329.60	-269.85
17.	मेघालय	-12.46	-12.97	-17.58
	जोड़	-2893.90	-3418.74	-4294.37

Purchase of Electricity from Nepal

2046. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to buy electricity from Nepal to meet the power demand; and

(b) if so, what are the salient features of the agreement, if any signed with the Government of Nepal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) and (b) Government of India and Government of Nepal have reached an understanding on an agreement to facilitate the process of electric power trade between the two countries. The proposed Agreement would enable devleopment of the considerable untapped hydro potential in Nepal.

Power crisis in Northern States

2047. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Northern States in the country have, of late, been facing power crisis and resorting to heavy load-shedding;

(b) if so, what is the percentage of rise in the power demand and the actual supply position in the northern states during 1995-96 (March) 1996 to March, 1977; and

(c) what measures have been taken by Government to meet the crisis?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) The constituent States of Northern Region faced an overall energy shortage of 13.3% and peaking shortage of 16.9% during the period April, 1996 to January, 1997. There being a gap in demand and supply of power, it is necessary to resort to power cuts/ restrictions to contain the demand within availability and to maintain the security of the grid.

(b) During the period April, 1996 to January, 1977, the energy requirement and availability in the States of Northern Region was 99254 MU and 91792 MU respectively as against the energy requirement and availability of 11976 MU and 105034 MU during the period April, 1995 to March, 1996.